भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2994

जिसका उत्तर 11 मार्च, 2026 को दिया जाना है ।

20 फाल्गुन, 1947 (शक)

बच्चों पर सोशल मीडिया के उपयोग का प्रभाव

2994. श्री पुट्टा महेश कुमारः

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विगत पांच वर्षों के दौरान बच्चों, विशेषकर स्कूल जाने वाली उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया के उपयोग के प्रभाव और उनके मानसिक स्वास्थ्य, अधिगम परिणामों और व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन, सर्वेक्षण/विशेषज्ञ आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग को कम करने के लिए ऐसे अध्ययनों के आधार पर किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) बच्चों पर सोशल मीडिया के प्रभाव के संबंध में माता-पिता/विद्यालयों के लिए पूरे भारत में आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार सोशल मीडिया प्लेटफार्मों तक बच्चों की पहुंच को सीमित करने/विनियमित करने के लिए किसी नीति, विनियामक ढांचे/सुरक्षा उपायों पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है जिसमें आयु के अनुरूप पहुंच नियंत्रण और प्रवर्तन तंत्र का ब्यौरा भी सम्मिलित हो?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ङ): सरकार की नीतियों का उद्देश्य बच्चों सहित अपने उपयोगकर्ताओं के लिए एक खुला, सुरक्षित और विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है।

अवसरों और संबंधित जोखिमों दोनों को स्वीकार करते हुए, सरकार ने डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बच्चों को हानिकारक सामग्री और पद्धतियों से बचाने के लिए श्रृंखलाबद्ध रूप से उपाय अपनाए हैं।

1. सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000

आईटी अधिनियम, 2000 और आईटी नियमों के तहत मध्यस्थों (सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म) से अपेक्षित है कि वे ऐसी सामग्री को होस्ट करने या साझा करने से रोकें जो बच्चों के लिए हानिकारक है या वर्तमान में लागू किसी भी कानून का उल्लंघन करती है।

प्लेटफ़ॉर्म को सरकार या अदालत के आदेश द्वारा अधिसूचित किए जाने के 3 घंटे (गैर-सहमति वाली यौन/अंतरंग सामग्री के लिए 2 घंटे) के भीतर गैरकानूनी सामग्री को हटाना होगा।

प्लेटफॉर्म भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, या यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 जैसे कानूनों के तहत संबंधित अपराधों के बारे में उपयुक्त अधिकारियों को रिपोर्ट करने के लिए भी बाध्य हैं।

2. बच्चों के डेटा का संरक्षण (डीपीडीपी अधिनियम, 2023)

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 और नियम, 2025 एक ऐसा ढांचा प्रदान करता है जिसमें प्रौद्योगिकियों के माध्यम से एकत्र किया गया व्यक्तिगत डेटा शामिल है।

यह किसी बच्चे के किसी भी व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने से पहले माता-पिता या वैध अभिभावक की सत्यापन योग्य सहमति को अनिवार्य करके बच्चों के व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिए विशेष सुरक्षा उपाय प्रदान करता है।

नियम सत्यापन योग्य माता-पिता की सहमति प्राप्त करने के लिए परिचालन तंत्र निर्धारित करते हैं, जिसमें पहचान और आयु सत्यापन उपाय और वर्चुअल टोकन का उपयोग शामिल है। बच्चों पर नज़र रखना, व्यवहार संबंधी निगरानी या लक्षित विज्ञापन भी प्रतिबंधित हैं।

3. इंडियाएआई मिशन के तहत सुरक्षित और विश्वसनीय स्तंभ

एआई के जिम्मेदार विकास, तैनाती और अंगीकरण को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा की आवश्यकता को चिह्नित करते हुए, सुरक्षित और विश्वसनीय एआई स्तंभ जिम्मेदार एआई परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सक्षम बनाता है।

इसमें स्वदेशी उपकरणों और रूपरेखाओं का विकास, नवप्रवर्तकों के लिए स्व-मूल्यांकन चेकलिस्ट और अन्य दिशानिर्देश और शासन ढांचे शामिल हैं। यह पूर्वाग्रह शमन, गोपनीयता-संरक्षण प्रणाली डिजाइन, एल्गोरिथम ऑडिटिंग टूल और जोखिम मूल्यांकन ढांचे पर केंद्रित परियोजनाओं का समर्थन करता है।
ये सुरक्षा उपाय नैतिक इरादे को लागू करने योग्य मानकों में परिवर्तित करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि एआई नवाचार विश्वसनीय, जिम्मेदार और सामाजिक रूप से लाभकारी बना रहे।

16 फरवरी, 2026 को इंडियाएआई मिशन के तहत शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी एआई रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेज अभियान का उद्देश्य पोर्टल (https://aipledge.indiaai.gov.in) के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक, समावेशी और जिम्मेदार उपयोग के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए देश भर के नागरिकों को संगठित करना था।

इस पहल ने प्रतिभागियों को डेटा गोपनीयता, जवाबदेही, पारदर्शिता और परिदृश्य-आधारित प्रश्नों के माध्यम से गलत सूचना से बचने जैसे प्रमुख सिद्धांतों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे एक भरोसेमंद और मानव-केंद्रित एआई इकोसिस्टम के निर्माण के भारत के दृष्टिकोण को मजबूत किया जा सके।

भारत ने 250,946 प्रतिज्ञाओं के साथ "24 घंटे में एआई रिस्पोंसिबल कैम्पेन के लिए प्राप्त सबसे अधिक प्रतिज्ञाओं" के लिए 'गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स' का खिताब भी हासिल किया है।

एम.ए.एन.ए.वी विजन

नई दिल्ली एआई इम्पैक्ट समिट में, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एआई के लिए भारत के एम.ए.एन.ए.वी विजन को प्रस्तुत किया।

यह एक रोडमैप प्रस्तुत करता है जहां तकनीकी प्रगति सामाजिक मूल्यों: नैतिक और नैतिक प्रणाली, जवाबदेह शासन, राष्ट्रीय संप्रभुता, सुलभ और समावेशी एआई, और वैध और वैध प्रणाली के अनुरूप आगे बढ़ती है।

सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता (आईएसईए)

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सूचना सुरक्षा में मानव संसाधन तैयार करने और जनता के बीच साइबर स्वच्छता और साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर सामान्य जागरूकता पैदा करने के लिए आईएसईए पर एक परियोजना लागू कर रहा है।
अब तक, देश भर में 4,309 जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं, जिनमें स्कूल/कॉलेज के छात्रों, शिक्षकों, कानून प्रवर्तन, सरकारी कर्मियों और आम जनता सहित 9.63 लाख से अधिक प्रतिभागियों को शामिल किया गया है।

स्कूली बच्चों और छात्रों के लिए 3.38 लाख प्रतिभागियों को शामिल करते हुए 1,186 जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। इसके अलावा, 1.13 लाख स्कूल शिक्षकों, पुलिस कर्मियों और स्वयंसेवकों को 66 कार्यक्रमों में मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया और लगभग 15 करोड़ अनुमानित लाभार्थियों को अप्रत्यक्ष मोड के माध्यम से कवर किया गया।

सीईआरटी-इन नियमित रूप से अपनी आधिकारिक वेबसाइटों और सोशल मीडिया हैंडल पर सुरक्षा और संरक्षा युक्तियाँ और जागरूकता पोस्टर, इन्फो-ग्राफिक्स और वीडियो साझा करता है और इसका उद्देश्य बच्चों के लिए ऑनलाइन सुरक्षा उपायों सहित साइबर सुरक्षा हमलों और धोखाधड़ी के विषय में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को संवेदनशील बनाना है।

*****